योजना

OJAANK IAS ACADEMY

SEPT, 2022 WWW.OJAANKEDU.COM *8750711100/44*

OJAANK IAS ACADEMY

Our Selected Students in IAS 2020

Congratulations to Our Toppers

01 Ranks in Top 10 | **10** Ranks in Top 50 | **26** Ranks in Top 100

RANK 01
SHRUTI SHARMA

RANK 58
FAIZAN AHMED

RANK 96
MINI SHUKLA

RANK 125
MD. MANZAR HUSSAN ANJUM

RANK 133
KISHLAY KUSHWAHA

RANK 176
SHREYA SINGHAL

RANK 203
MOHAMMAD AAQUIB

RANK 270
HARIS SUMAIR

RANK 283
AHMED HASANUZZAMAN CHAUDARY

RANK 389
MOHIBULLAH ANSARI

RANK 447
FAISAL RAZA

हिंदी साहित्य
द्वारा : श्री समीरात्मज मिश्रा
प्रख्यात लेखक एवं पूर्व BBC पत्रकार
निबंध मंजूषा McGraw Hill
बम्पर ऑफर
कक्षा कार्यक्रम- 45,000 30,000/-
Live/Online Fees- 40,000
प्रथम 100 छात्रों के लिए 30,000/-
www.ojaankedu.com
निबंध मंजूषा
Ojaank Sir
द्वारा : श्री समीरात्मज मिश्रा
Live On
ojaankEDU APP
App Store
Google Play
18/4, 3rd Floor Opposite Aggarwal Sweet
Near Gol Chakkar, Old Rajinder Nagar, New Delhi.
8750711100/22/33/44
7678528990

1YEAR COMPLETE
YOJANA &
Kurukshetra
Discount
Fee- 2000/-
1500/
Recorded Class
Limited
Offer
UPSC CSE 2021-2022
AIR-1 (SHRUTI SHARMA)
18/4, 3rd Floor Opposite Aggarwal Sweet, Near
Gol Chakkar Old Rajinder Nagar, New Delhi.
www.ojaankedu.com
Google Play
App Store
8750711100/22/33/44, 76785 28990

इतिहास
SPECIAL OFFER
वैकल्पिक विषय
निर्देश भारद्वाज सर के द्वारा
Classroom Fees - 45,000 30,000/-
Online/ Live - 40,000 30,000/-
LIVE ON ojaankEDU APP
Google Play
App Store
ऑनलाइन/कक्षा कार्यक्रम
18/4, 3rd Floor Opposite Aggarwal Sweet
Near Gol Chakkar Old Rajinder Nagar
New Delhi.
www.ojaankedu.com
8750711100/22/33/44, 7678528990
Our Topper (Air-1)
Optional History
Ojaank IAS Academy

SOCIOLOGY
OPTIONAL
Ojaank IAS Academy
By Ankur Aggarwal Sir
BUMPER OFFER
FEE Discount For 100 Students
Classroom Fees - 45,000 30,000/-
Online/ Live - 40,000 30,000/-
Online/Classroom
UPSC CSE 2021-2022
AIR-1(SHRUTI SHARMA)
18/4, 3rd Floor Opposite Aggarwal Sweets
Near Gol Chakkar Old Rajinder Nagar, New Delhi.
8750711100/22/33/44, 7678528990
Google Play
App Store
www.ojaankedu.com

TARGET UPSC PRELIMS (GS) 2023
एक बार TRY तो बनता है
आज का ऑफर
SCAN THE QR CODE
TO PAY
Offer Valid 28-09-22
रात 12 बजे तक
₹99/- Only
UPSC 2021
AIR-1
SHRUTI SHARMA
Online/ Live
Bilingual
Batch Start From
15 Nov 2022
www.ojaankedu.com
8750711100/22/33/44, 7678528990

OJAANK IAS ACADEMY
ADVANCE
NCERT
PRELIMS TEST SERIES
Was 2999/-
499/-
OUR TOPPERS
SHRUTI SHARMA
87-50-7-111-00/22/33/44, 76-785-289-90
Website : www.ojaankedu.com
REGISTER NOW

निवेश को प्रोत्साहन

- केंद्र सरकार ने तीन साल पहले विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं के अंतर्गत 'संविधान के समय-समय पर संशोधित प्रावधानों सहित सभी प्रावधान' जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू कर दिए। साथ ही, पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य का निम्न दो केंद्र-शासित क्षेत्रों में पुनर्गठित कर दिया- लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर। दीर्घकालीन नीति इस क्षेत्र और इसकी अर्थव्यवस्था में आमूल बदलाव लाने की थी।
- 2018-19 में जम्मू और कश्मीर सरकार का व्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 57 प्रतिशत था जिसके लिए अधिकतर धन केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा था।
- सरकार पर निर्भरता बहुत अधिक थी और निजी क्षेत्र कमजोर था। (लगभग समान विशेषताओं वाले हिमाचल प्रदेश में सरकारी व्यय मात्र 28 प्रतिशत था।) उस समय, तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की प्राप्तियों का 40 प्रतिशत केंद्र सरकार से मिलता था।
- बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों (करीब 5 लाख) के होने से राज्य की कुल प्राप्तियों का एक चौथाई वेतन और पेंशन में चला जाता था। जम्मू और कश्मीर का प्रति व्यक्ति नेट घरेलू उत्पाद करीब 94,000 रुपये था जो हिमाचल प्रदेश के 1,76,000 रुपये की तुलना में करीब आधा था।
- जम्मू और कश्मीर में सड़कों का घनत्व हिमाचल प्रदेश की तुलना में पाँचवाँ हिस्सा था और हिमाचल प्रदेश के विपरीत, जम्मू और कश्मीर अपनी विशाल जल-विद्युत क्षमता का भी उपयोग नहीं कर पा रहा था।
- यह टिकाऊ स्थिति नहीं था और इसे बदलना ज़रूरी था। जम्मू और कश्मीर को ऐसी स्थिति में लाना ज़रूरी था ताकि निजी उद्यम और निवेश यहाँ आएं और ज्यादा नौकरियाँ तथा आय सृजित होने से अर्थव्यवस्था मजबूत हो। ऐसे बदलाव के लिए उपयुक्त आर्थिक रणनीति ज़रूरी थी।

आर्थिक नीतियों का निर्माण

- **किसी क्षेत्र के लिए उचित आर्थिक नीति के निर्माण के लिए उस क्षेत्र की सकारात्मक और नकारात्मक स्थितियों का जायजा लेना जरूरी होता है। यह बात जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होती है।**
- **जम्मू और कश्मीर की स्थिति और भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ उत्पादित वस्तुओं की परिवहन लागत अधिक होगी जिससे उनकी कीमत भी बढ़ेगी। इसलिए महंगी वस्तुओं के कारोबार के लिए उचित आर्थिक रणनीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें निवेशकों तथा नीति-निर्माताओं को इस तरह निर्देशित किया जाए कि वे ऐसी विशिष्ट वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन को बढ़ावा दें जो ऐसे खास ग्राहकों की पसंद की हों जो परिवहन लागत के कारण अधिक कीमत होने पर भी इन वस्तुओं/सेवाओं को खरीदें।**
- **ऐसे अनेक उत्पाद/सेवाएँ हो सकती हैं जिनका क्षेत्र-विशेष में उत्पादन/निर्माण दीर्घ कालावधि में सम्बन्धित कौशल। स्थानीय जानकारी के विकास से संभव हुआ है और उस क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति की वजह से स्वाभाविक रूप से वहाँ वह उत्पादन/निर्माण होता हो।**
- **जम्मू और कश्मीर में अनेक उत्पादों/सेवाओं से सम्बन्धित कौशल और स्वाभाविक स्थितियाँ मौजूद हैं और उनपर ध्यान दिए जाने से इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बदलाव की शुरूआत हो सकती है।**
- **जहां तक स्थानीय उत्पादों का प्रश्न है, इस क्षेत्र के हस्तशिल्पों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है। जम्मू और कश्मीर में बड़ी मात्रा में सेब पैदा होता है और यहाँ अखरोट और केसर जैसे उत्पाद भी हैं जो जिनका आकार और वजन कम लेकिन कीमत ज्यादा होती है।**

निवेश को बढ़ावा

- जम्मू और कश्मीर औद्योगिक नीति - 2021-30 इस केंद्र-शासित क्षेत्र में निवेश तथा औद्योगिक वृद्धि की अग्रणी नीति है। नई औद्योगिक विकास योजना अपनी तरह की सबसे आकर्षक योजना तो है ही, बल्कि इसमें पिछली योजनाओं की कमियाँ भी दूर की गई हैं। इसमें दूर-दराज के इलाकों को अधिक प्रोत्साहन देने का प्रावधान है जिससे विकास को बल मिलेगा और अब तक उपेक्षित क्षेत्रों में खान" जमीन का बेहतर उपयोग हो सकेगा।
- इस नीति में निवेश, वटि रोजगार- इन सभी पक्षों पर विवेकपूर्ण तरीके से ध्यान दिया गया रोजगार पैदा करने के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। इस में ऐसे उद्योगों पर जोर दिया गया है जिनमें ज्यादा श्रमिक काम सके और तैयार होने वाला उत्पाद ज्यादा मूल्य और गुणवत्ता काही इनमें इस केंद्र-शासित क्षेत्र के पारम्परिक रूप से सशत उद्योग, जैसे पर्यटन, हस्तशिल्प और बागवानी तो शामिल हैंडी सचना प्रौद्योगिकी तथा इससे जुडी सेवाएँ और स्वास्थ्य सेवा और शामिल हैं।
- इस नीति में वर्तमान सशक्त उद्यमों से जुड़े क्षेत्रों के विकास पर भी ध्यान दिया गया है- जैसे बागवानी में फसल तैयार होने के बाद उसके प्रबंधन से जुड़े काम तथा फिल्म पर्यटन जैसे पर्यटन के विविध रूप आदि।
- पिछली नीतियों में राज्य में निवेश लाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्सिडी और करों में छूट दी गई। लेकिन वित्तीय प्रोत्साहनों पर आधारित ऐसे अनेक निवेशों को उन क्षेत्रों से नहीं जोड़ा गया जिनमें जम्मू और कश्मीर स्वाभाविक रूप से सशक्त था।
- नई नीति में उन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है जिनमें राज्य की स्थिति स्वाभाविक रूप से अच्छी है। सेवा क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का 53 प्रतिशत हिस्सा है इसलिए इस नीति में एक स्पष्ट सकारात्मक सेवा क्षेत्र सूची बनाई गई है जिसमें शामिल उद्यमों को प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इनमें पर्यटन, फिल्म पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा और कौशल विकास आदि शामिल हैं।
- इस औद्योगिक नीति के प्रारम्भ के बाद की नीतिगत घोषणाओं और बजट प्रावधानों में इसी नीति के मूलभूत पक्षों को ही सशक्त किया गया है। उक्त घोषणाओं और बजट प्रावधानों का उद्देश्य इसी नीति के विविध पक्षों का विस्तार करना और उन्हें सशक्त बनाना है।

पर्यटन

- जम्मू और कश्मीर को लंबे समय से पर्यटन के साथ जोड़ा जाता है लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि पर्यटकों की कुल संख्या अथवा जनसंख्या के अनुपात में पर्यटकों की आमद के मामले में यह तत्कालीन राज्य कभी भी देश के चोटी के दस राज्यों में नहीं रहा।
- इस केंद्र-शासित क्षेत्र के वर्तमान बजट में 75 नए पर्यटन-केन्द्रों के लिए मदद और संसाधन दिए गए हैं ताकि क्षेत्र की पर्यटन अर्थव्यवस्था का विस्तार हो और बहुत अधिक रोजगार की संभावना वाले इस क्षेत्र में ज्यादा रकम आए। इससे जुड़े दूसरे विभागों के कार्यों और उनको दिए गए वित्तीय प्रावधानों के साथ समझदारी से ताल-मेल बिठाया जा रहा है, जैसे संस्कृति विभाग परम्परागत मेलों और सूफी समारोहों को नए सिरे से प्रोत्साहित कर रहा है।
- इनमें से अनेक दूर-दराज के अनजान इलाकों में हैं जो जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण पर्यटन नेटवर्क का हिस्सा हैं। इनसे स्थानीय यवाओं को प्रोत्साहन और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इन प्रयासों के साथ तालमेल से बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है।
- पिछले वर्ष नवंबर में जम्मू और कश्मीर में पिछले सात वर्षों में सबसे अधिक संख्या में पर्यटक आए। 27 मार्च को 36,473 पर्यटक ट्यूलिप गार्डन देखने आए। यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इस वर्ष 4 अप्रैल श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के इतिहास में व्यस्ततम दिन रहा। उस दिन 90 उड़ानों में 15,014 लोग या तो श्रीनगर आए या यहाँ से गए।

बागवानी

- बागवानी के लिए बजट में उत्पादकता और आमदनी- दोनों बातों पर ध्यान दिया गया है। बजट में प्रोत्साहित किए गए क्षेत्रों में शामिल हैं- कोल्ड स्टोरेज की क्षमता को बढ़ावा देना ज्यादा बगीचे लगाकर सेब की उत्पादकता बढ़ाना, कम जगह में आ जाने वाले और ज्यादा दाम देने वाले कृषि-उत्पादों, जैसे सुगंध वाली और नकदी फसलों तथा सब्जियों को प्रोत्साहित करना आदि।
- केसर और अन्य उत्पादों के लिए जीआई प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। इन प्रयासों से इस क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ेगी। अगर इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादकता बढ़ सकेगी तो इस क्षेत्र का विस्तार चार गुना हो जाएगा।

COPYING@OJAANKIAS

विदेश व्यापार और निवेश

- जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने एक और पहल की है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच पिछले दिनों व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) हुआ है। इसमें कारोबार के लिए बाजार, निवेश और पर्यटन का विस्तार करने के प्रावधान हैं।
- जम्मू और कश्मीर को इस समझौते से लाभान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यूएई कश्मीर से घनिष्ठता के साथ सुपरिचित है। अतः इन संपर्कों और संभावनाओं का लाभ उठाते हुए, खाड़ी क्षेत्र से निवेश प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जम्मू और कश्मीर में निवेश बढ़ाना

- इस क्षेत्र में संवैधानिक अनिश्चितता समाप्त होने, कानून और व्यवस्था की बेहतर स्थिति, मूलभूत सुविधाओं पर बहुत अधिक ध्यान दिए जाने तथा आर्थिक विकास पर केन्द्रित कार्य-नीति अपनाए जाने से निवेशकों की इस क्षेत्र में दिलचस्पी बढ़ी है और अनेक नीतियों के प्रति उनका रुख उत्साहजनक रहा है।
- जो निवेशक पहले तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य में निवेश करने से कतराते थे, वे अब नवगठित केंद्र-शासित क्षेत्र में निवेश करने के लिए उत्साहित नज़र आ रहे हैं। यहाँ के प्रशासन को 51,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं जिनसे 2.37 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।
- यह भी महत्वपूर्ण है कि अब इस क्षेत्र में विदेशी, खास तौर से यूएई के सुपरिचित नामों और ब्रांडों की दिलचस्पी बढ़ी है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जिन क्षेत्रों में निवेश की पेशकश हुई है और प्रस्ताव मिले हैं उनमें से अधिकतर सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सकारात्मक क्षेत्रों की सूची में शामिल हैं।

लाभदायक क्षेत्रों में निवेश की रणनीति

- जम्मू और कश्मीर में धन लगाने से पहले निजी निवेशक क्या अपेक्षा रखता है? इसका स्पष्ट उत्तर यही है कि उसे उसके निवेश पर लाभ मिले। इसके किए ज़रूरी है कि निवेशक की व्यावसायिक योजना राज्य की प्राकृतिक, पारम्परिक और मानव संसाधनों से कितनी घनिष्ठता से जुड़ी है।
- एक सुव्यवस्थित कारोबार ऐसे ही पुख्ता आधार पर लाभदायक बना रहता है, हमेशा सरकारी सब्सिडी के भरोसे नहीं टिका रहता। जम्मू और कश्मीर में पिछले दिनों पर्यटकों की भीड़ ने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। इससे पता चलता है कि यह क्षेत्र निवेशकों के लिए कितना लाभदायक हो सकता है। इसलिए, इस क्षेत्र में, खास कर अब तक अनजाने रहे इलाकों में, निवेश करना काफी लाभदायक हो सकता है।
- बागवानी और फसल के बाद उत्पाद के मूल्य-संवर्धन की प्रक्रियाओं में निवेश भी फायदेमंद हो सकता है। इन दोनों क्षेत्रों में यह केंद्र-शासित क्षेत्र प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, साथ ही इन उद्यमों के बारे में स्थानीय लोगों को जानकारी भी है और ये पारम्परिक क्षेत्र भी हैं।
- निवेशक मुनाफे की अच्छे संभावनाओं वाले अनेक अन्य क्षेत्रों में भी निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सूचना टेक्नोलॉजी और इससे जुड़ी सेवाओं में बड़ी संख्या में कुशल स्थानीय युवाओं को काम पर लिया जा सकता है।
- सूचना टेक्नोलॉजी की प्रगति तथा कोविड-19 की वजह से, इस क्षेत्र में घर से ही काम करने का रुझान बढ़ गया है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए इस क्षेत्र में निवेश में मुनाफे की अच्छी संभावनाएं हो गई हैं।
- जम्मू और कश्मीर में ऐसे ही नवीन संभावनाओं वाले क्षेत्रों में सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य और समग्र आरोग्य से जुड़े उद्यम शामिल हैं। लेकिन मात्र सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए जम्मू और कश्मीर में निवेश करना अविवेकपूर्ण होगा और इससे लंबे समय में नकसान ही होगा।
- उज्ज्वल भविष्य की ओर सरकार की आर्थिक नीति का उद्देश्य ऐसा बदलाव लाना है जिसमें नया जम्म और कश्मीर निरंतर प्रगतिशील भारत के साथ-साथ चले और जहां घूमने तथा संभावनाएं तलाशने के नए-नए इलाके हों।

COPYING@OJAANKIAS

- यहाँ का बागवानी क्षेत्र ऐसे फल उपजाए और फलों से बनने वाले उत्पाद तैयार करे जो गुणवत्ता में विश्व-स्तर के हों। सदियों के अनुभव और संस्कृति के बीच विकसित यहाँ के हस्तशिल्पों का दुनिया भर में नई ऊर्जा से निर्यात किया जाए। इस क्षेत्र को भारत की एक-तिहाई जल-विद्युत पैदा करनी होगी।
- इस क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और सम्बन्धित सेवाओं, औषधि उद्योग, वन उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के विकास की भी बहुत संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य, आरोग्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी यह क्षेत्र देश भर में बेजोड़ हो सकता है।

जीवन-यापन में सुगमता

- अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक सुधार होने के बाद से सरकार अभूतपूर्व गति से क्षेत्र के लोगों के लिए शासन में सुधार और जीवन यापन को सुगमता बढ़ाने के लिए व्यापक सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बनिहाल का गुंड सुरंग का निर्माण 3.100 करोड़ रुपये की लागत सं किया गया है और यह चालू हो गया है।
- 8.45 किलोमीटर लंबी इस सुरंग के बनने के बाद बनिहाल और काजीगुंड के बीच की दूरी 16 किलोमीटर तक घट गई है और यात्रा के समय में डेढ़ घंटे की बचत होगी। इस सुरंग से किसी भी मौसम में जम्मू और कश्मीर का संपर्क बना रहेगा और दोनों क्षेत्रों के बीच दूरी कम करने में मदद मिलेगी।
- प्रधानमंत्री ने जम्मू के पल्ली गांव में 500 किलोवाट के सौर ऊजा संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस तरह यह देश की पहली कार्बन मुक्त पंचायत होगी।

मौजूदा सड़क और परिवहन परियोजनाएं

बारामुला-गुलमर्ग

- जन्मू-कश्मीर केंद्रशासित क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-701 ए के तहत मौजूद सड़कों को अपग्रेड करना। कुल लंबाई 43 किलोमीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग की गुणवत्ता में सुधार के लिए 85 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया। इससे गुलमर्ग जाने वाले सैलानियों को सहुलियत होगी।

वेलू से दोनीपावा (पी-VT):

- जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-244 से जुड़ी सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण। कुल लंबाई 28 किलोमीटर, जिसके लिए 158 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके जरिये कोकरनाग और वेलू का संपर्क बेहतर हो सकेगा।

दोनीपावा से आशाजीप्रा (पी-VII):

- अनंतनाग में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-244 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 से जोड़ा जाएगा। नए बाईपास का निर्माण होगा। सड़क की कुल लंबाई 8.5 किलोमीटर है और अनंतनाग शहर के पास बाइपास बनाने के लिए 57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- श्रीनगर के आसपास 4 लेन वाले रिंग रोड का निर्माण (42 किलोमीटर), श्रीनगर शहर में भीड़-भाड़ और ट्रैफिक को कम करने के लिए 2948.72 करोड़ रुपये आवंटित किए श्री अमरनाथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो।
- केंद्र की योजना 'प्रसाद' के तहत, दरगाह हज़रतवल में पर्यटक प्रस्तुतीकरण केंद्र (टूरिस्ट इंटरप्रिटेशन सेंटर) का निर्माण कार्य पूरा हा चुका है।
- केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए 19 फरवरी 2021 को नई योजना की शुरुआत की थी, जिस पर कुल 28,400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका मकसद जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास को बढावा देना इस योजना से 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना स्वच्छ भारत मिशन के तहत जम्मू-कश्मीर को खुले में शौच समस्या से मुक्त कर दिया गया है।

COPYING@OJAANKIAS

- सौभाग्य, उजाला, उज्ज्वला और इंद्रधनुष समेत केंद्र की कुल-व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं में सफलता का शत-प्रतिशत लश हासिल कर लिया गया है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक 14500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके तहत, 2,000 जगहों को बेहतर सड़कों से जोड़ा गया है।
- जम्मू और श्रीनगर से रात्रिकालीन उड़ान सेवाएं भी शुरू की गई हैं। सेव के लिए शुरू की गई उच्च-घनत्व पौधारोपण योजना का दायरा वढ़ाकर अब इसमें आम, लीची, चेरी, काजू आदि फलों को भी शामिल किया गया है। कश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया गया है।
- जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित क्षेत्र में साल 2019 से अब तक विभिन्न क्षेत्रों योजनाओं के तहत कुल 141,815 कार्यो/परियोजनाओं को शुरू किया गया है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 27274 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है।
- कौशल से लैस कर्मचारियों के अलावा अकुशल मजदूरों, छोटे कारोबारियों, माल ढुलाई करने वालों, इंजीनियरों और अलग-अलग तरह की सामग्री की आपूर्ति करने वालों को भी इसका फायदा मिल रहा है।
- एक अनुमान के मुताबिक, इस निवेश से 1,169 लाख श्रम दिन का रोजगार सृजित हुआ। आधारभूत संरचना से जुड़े क्षेत्रों की स्थिति के बारे में नीचे बताया गया है:

1. पीएमडीपी-2015 – जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित क्षेत्र में पीएम विकास पैकेज 2015 के तहत चल रही परियोजनाओं पर काम तेज़ हुआ है। सड़क, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, कौशल विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 58,477 करोड़ की लागत से कुल 53 परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। ये परियोजनाएं 15 मंत्रालयों से संबंधित हैं।
2. देरी से चल रही परियोजनाएं- इस श्रेणी में आने वाली कुल 1.193 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जिनकी कुल लागत 1984 करोड़ रुपये हैं।
3. स्वास्थ्य- हाल में 2 नए एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 राज्य स्तरीय कैंसर संस्थान और 15 नर्सिंग कॉलेजों को चालू किया गया है।
4. जल जीवन मिशन- पहले जहां कुल 5.75 लाख घरों (31 प्रतिशत) में पानी की कनेक्शन था, वहीं अब कुल 10.55 लाख घरों (57 प्रतिशत) में पानी का कनेक्शन है। दो जिलों (श्रीनगर और गांदरबल) को हर घर जल जिला भी घोषित किया जा चुका है।
5. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण- तीन अहम सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके तहत, मुख्य रावी नहर (लागत 62 करोड़ रुपये) परियोजना, त्राल लिफ्ट सिंचाई परियोजना (लागत 45 करोड़ रुपये) के तीसरे चरण और झेलम और उसकी सहायक नदियों से जुड़ी बाढ़ प्रबंधन योजना के पहले चरण को पूरा किया गया है।
6. शिक्षा- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), जम्मू और भारतीय प्रबंधन संस्थान, जम्मू का संचालन शुरू हो गया है। सरकारी डिग्री कॉलेजों/इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बढ़कर 96 से 147 हो गई हैं।

सतत पर्यटन

- भारत पारिस्थितिकीय दृष्टि से सर्वाधिक विविधताओं वाले देशों में से एक है, जिसमें शानदार पहाड. महासागर, आकर्षक रेगिस्तान और समृद्ध वन शामिल हैं। ऐसी ही एक खास जगह अत्यंत ऊँचाई पर स्थित लद्दाख का रेगिस्तान है, जिसे आमतौर पर 'मन लैंड' कहा जाता है, जो भारत के सबसे उत्तरी दूरस्थ स्थान में स्थित है।
- यह स्थान बेहद ऊँचे पहाड़ों और ठंडे रेगिस्तानी मैदानों के जादुई परिदृश्य में स्थित कुछ अत्यंत खूबसूरत और प्राचीन मठों के लिए विख्यात है। लद्दाख अपने स्थान और सुदूरता के कारण पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील जगह है, जो अपने पर्यटन उद्योग से लाभ प्राप्त करता है।
- परिवहन, आवास, खानपान, कुटीर उद्योग आदि जैसे सम्बन्धित उद्योगों में काम करने वाले बहुत से अन्य लोगों को पर्यटन व्यवसाय में काम करने के अवसर मिलते हैं लेकिन, दुर्भाग्यवश, इसकी वजह से इस संवेदनशील पारिस्थितिकीय तंत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत

COPYING@OJAANKIAS

दबाव पड़ता है। इसे और गति देने के लिए, जलवायु परिवर्तन का अत्यधिक प्रभाव भी यहां लोगों की जान को बहुत बड़े जोखिम में डाल रहा है।

- वर्षा भी अविश्वसनीय रूप से अनियमित हो गई है। लेह लद्दाख क्षेत्र में बादल फटने के कारण अचानक आने वाली बाढ़ भी लद्दाख के दीर्घकालिक टिकाऊ होने पर संदेह उत्पन्न कर रही है।
- लद्दाख सरकार ने पर्यावरण की रक्षा, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बरकरार रखने के लक्ष्य के साथ अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य आरंभ किया है।
- केंद्र सरकार साहसिक, संस्कृति और जिम्मेदार पर्यटन के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए लद्दाख को पर्यटक स्थल बनाने की दिशा में काम कर रही है। पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत 'स्वदेश दर्शन' और 'प्रसाद' योजनाओं के तहत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए 594 करोड़ रुपये की सात परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- यह कदम लद्दाख को स्थानीय समुदाय के लिए स्थायी और समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण, पारिस्थितिकीय दृष्टि से सतत पर्यटक स्थल (लो-इम्पैक्ट टूरिज्म) बनाएगा।
- यह बात ध्यान में रखना होगी कि पर्यटन की प्रकृति टिकाऊ होनी चाहिए तथा व्यवस्थित और नियंत्रित पर्यटन के माध्यम से इसका स्थानीय पारिस्थितिकी और आबादी पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव होना चाहिए।
- लद्दाख में पर्यटन को प्रोत्साहन देने का उद्देश्य स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना तथा भारत और शेष विश्व के पर्यटकों के बीच लद्दाख की संस्कृति और उत्पादों को बढ़ावा देना है।
- **विकास के नए अवसरों, कनेक्टिविटी, बुनियादी सुविधाओं तथा टिकाऊ और समुदाय-आधारित विकास पर ध्यान देते हुए लद्दाख के पर्यटन उद्योग को समग्र रूप से विकसित किया जाना बहुत आवश्यक है। यहाँ अवसर और चुनौतियाँ अपार हैं, जो लेह में साहसिक पर्यटन रूप में मौजूद हैं, नई संभावनाओं के द्वार खोलने तथा स्थानीय समुदाय और विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाने आदि का सामर्थ्य होमस्टे पर्यटन में मौजूद हैं।**
- **जम्मू, कश्मीर और लद्दाख तीन अलग-अलग क्षेत्र हैं, जो मिलकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का निर्माण करते हैं। इन तीनों क्षेत्रों में देशी और विदेशी पर्यटकों की बदौलत पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।**
- **कश्मीर को अक्सर 'धरती पर स्वर्ग' की उपमा दी जाती है और यह लंबे अर्से से एक प्रमुख पर्यटन स्थल रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य की प्रचुरता के कारण इसे 'पूर्व का स्विट्जरलैंड' भी कहा जाता है।**
- **ऐसे उत्पाद बहुतायत में हैं, जिन्हें जम्मू और कश्मीर राज्य में खरीदा जा सकता है। राज्य के प्रत्येक जिले में आगंतुकों के लिए प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन, साहसिक पर्यटन (जैसे रिवर राफ्टिंग और पर्वतारोहण), अनेक ट्रेकिंग रूट, तीर्थयात्रा पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन, विरासत पर्यटन, जातीय खाद्य उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम, हस्तशिल्प आदि सहित बहुत कुछ मौजूद है।**
- **पर्यटन में अभूतपूर्व वृद्धि ने इस स्थान पर 'अति-पर्यटन' (यानी ओवर टूरिज्म) को जन्म दिया है, जिसका प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और जीवन की गुणवत्ता पर तत्काल नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।**
- **यदि खराब प्रबंधन वाले 'अति-पर्यटन' को संभावित जोखिम के रूप में देखा जा रहा है, तो पर्यटन को बहुधा संचालित करने वाली गतिशील ताकतों का नकारात्मक प्रभाव अपरिहार्य हो जाता है। एक सतत संरचना में, पर्यटन के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक-सांस्कृतिक परिणामों के बीच संतुलन होना चाहिए।**

यूएनडब्ल्यूटीओ के अनुसार, सतत पर्यटन:

- महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं को बरकरार रखते हुए तथा प्राकृतिक विरासत और जैव विविधता के संरक्षण में सहायता देते हुए, पर्यटन के विकास के लिए महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है;

- मेजबान समुदायों की सामाजिक-सांस्कृतिक प्रामाणिकता का सम्मान करता है, उनकी निर्मित और सजीव सांस्कृतिक विरासत और पारम्परिक मूल्यों को संरक्षित करता है, और अंतरसांस्कृतिक समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है।
- दीर्घकालिक आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करता है, स्थायी रोजगार और आय के सृजन के अवसरों सहित सभी हितधारकों को संतुलित तरीके से सामाजिक-आर्थिक लाभ वितरित करता है, मेजबान समुदायों के लिए सामाजिक सेवाओं और गरीबी में कमी लाने में सहायता करता है।
- लद्दाख जैसे स्थानों में पर्यटन उद्योग प्राचीन प्राकृतिक स्थान की छवि प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है, लेकिन इन क्षेत्रों में आने वाले अधिकांश आगंतुक इसके संवेदनशील पारिस्थितिकीय तंत्र और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के प्रति बहत सम्मान दिखाते हैं।
- हर साल, वे टनों कचरा उत्पन्न करते हैं, पर्यावरण और मानव स्वास को खतरे में डालने के साथ ही साथ स्थान की सुंदरता को बर्बाद कर देते हैं।
- वर्तमान समय में ऐसी रणनीति अपनायी जानी चाहिए जो प्रदूषण के खतरे और पर्यावरणीय क्षरण के जोखिम में पर्याप्त कमी लाए और पर्यटन का विकास वहन करने की क्षमता पर आधारित हो।

उच्च गुणवत्ता सम्पन्न पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण की क्षमता का दोहन

- वैज्ञानिक समझ और कुशल योजना के माध्यम से किया जाना अभी बाकी है। लद्दाख का परिदृश्य मुख्य रूप से चरागाहों/घास के मैदानों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो पशुपालन उत्पादों पर निर्भर जातीय समुदायों के घर हैं।
- ये चरागाह प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के समूह को दर्शाते हैं। हालांकि इन परिदृश्यों के विभिन्न घटकों के नाजुक अंतर्संबंधों को उचित रूप से समझे बिना, पर्यटन का त्वरित विकास लद्दाख के इन विलक्षण घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकता है।
- लद्दाख परिदृश्य के इन क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए निरंतरता की संभावनाओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है। सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा, सीमित संसाधनों का गहन उपयोग और बाकी स्थानों की ही तरह नकारात्मक बाह्यता के यहां भी कई अन्य हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि पारम्परिक पर्यावरण के अनुकूल और सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक वास्तुकला को अनुचित, संसाधनों के अतिशय इस्तेमाल वाले और खतरनाक निर्माणों, खराब डिजाइन वाली सड़कों और अन्य सम्बन्धित बुनियादी सुविधाओं, अपर्याप्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बढ़े हुए वायु प्रदूषण, जल स्रोतों में गिरावट और जैविक विविधता के नुकसान से बदल देना।
- केवल ज्यादा से ज्यादा आगंतुकों को आकर्षित करने पर ही ध्यान केंद्रित करना सतत पर्यटन विकास का आधार नहीं हो सकता, खासकर तब, जबकि क्षेत्र की वहन क्षमला सीमित हो।
- लद्दाख क्षेत्र की विशिष्टता और संवेदनशीलता की विशेषताओं को देखते हुए पर्यटक विकास का फोकस पर्यटन की गुणवत्ता और स्थानीय समुदायों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच पर्यटन से होने वाली आय में समानता पर हो सकता है।
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को 'इको-टूरिज्म हॉटस्पॉट' के रूप में विकसित करने के दिशा में कड़ा परिश्रम करना होगा, क्योंकि अनियंत्रित पर्यटन जलवायु परिवर्तन के कारण उपजे पारिस्थितिकीय असंतुलन में योगदान देता है।
- पारिस्थितिकीय पर्यटन या इकोटूरिज्म प्राचीन क्षेत्रों की नीतिपरक यात्रा (इथिकल ट्रैवल) है, जो पर्यावरण की रक्षा करती है, सामुदायिक विकास को बढावा देती है तथा स्थानीय लोगों और आगंतुकों दोनों शिक्षित करती है।
- यह केंद्र शासित प्रदेश उत्साह किए गए कार्बन से अधिक मात्रा में कार्बन अवशोषित करने और वैश्विक ग्रीनहाउस और के लिए नेट सिंक होने का संकल्प लेने वाले भूटान के साथ ही साथ अन्य पर्यटक हॉटस्पॉटस से जानकारी एकत्र कर सकता है। उदाहरण के लिए, आगंतुकों की संख्या सीमित करने, पर्यावरण के अनुकूल उच्च गुणवत्ता वाली इको-लॉज का निर्माण करने और विदेशी वन्यजीवों के अवैध शिकार में कमी लाने, जैसे कदम संभवतः इन क्षेत्रों में विकास और पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में बनाए जाने वाले कड़े नियमों और दिशानिर्देशों का हिस्सा हो सकते हैं।
- निरंतरता की दिशा में इन संतुलित प्रयासों को अपनाकर हम प्राकृतिक पर्यावरण और पारिस्थितिकी की रक्षा करके इन स्थानों की सुंदरता को बरकरार रख सकते हैं।

COPYING@OJAANKIAS

शिक्षा और कौशल विकास

- लद्दाख को 2019 में संघ शासित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद से अनूठे प्राकृतिक संसाधनों, बेहतरीन पर्यावरण और मिलनसार आबादी वाले इस क्षेत्र के लिये प्रचुर अवसरों के द्वार खुल गये हैं।
- केंद्र सरकार से मिल रहे धन तथा केंद्रीय और संघ शासित क्षेत्र स्तरीय नेतृत्व के प्रयासों ने लद्दाख प्रशासन को अवसर दिया है कि वह इस शांत और बेहद खूबसूरत क्षेत्र में विकास का एक विशिष्ट मॉडल तैयार कर लागू करे।
- विकास के किसी भी मॉडल के लिये प्रशासन की योजना में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। लिहाजा, लद्दाख के युवाओं को जरूरी कौशलों और क्षमता से लैस करना महत्वपूर्ण है ताकि वे एक अनुकरणीय मॉडल पेश करते हए क्षेत्र को विकास के पथ पर आगे ले जा सकें।
- मौजूदा समय में इनमें से लगभग 3938 युवा महाविद्यालयों, पॉलीटेकनिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा लद्दाख के लगभग इतने ही युवा इस संघ शासित क्षेत्र के बाहर उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत हैं।
- लद्दाख के बाहर पढ़ने वाले स्थानीय युवा लौट कर सरकारी नौकरियों तथा पर्यटन और इससे सम्बन्धित उद्योगों में लग जाते हैं। लद्दाख में उद्योगों की मौजूदगी बहुत कम है।
- इसलिये युवाओं की वापसी से इस संघ शासित क्षेत्र के सीमित रोज़गार बाजार पर दबाव बढ़ता है। लेकिन ये शिक्षित युवा अपने साथ अनुभव, विचार और उद्यमिता भी लाते हैं जिससे क्षेत्र को नये अवसरों के इस्तेमाल में मदद मिल सकती है।
- लद्दाख प्रशासन ने पिछले ढाई वर्षों में इस जनसांख्यिकीय लाभ का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया है। वह युवाओं के क्षमता निर्माण के लिये प्रयासरत है ताकि वे क्षेत्र के संवहनीय विकास में सक्रिय योगदान कर सकें।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मददगार अवसंरचना

- लद्दाख में गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लद्दाख विश्वविद्यालय की स्थापना 2019 में की गयी और इसके अंतर्गत लेह, कारगिल, नुबरा, जस्कार, खालसी और द्रास के छह महाविद्यालय आते हैं।
- वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में 22 विभाग हैं तथा अपराध विज्ञान, पुलिस प्रशासन और शारीरिक शिक्षा जैसे विशिष्ट विषयों की भी पढ़ाई की जा रही है। लद्दाख विश्वविद्यालय ने छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रमों, संकाय विकास, अनुसंधान में सहयोग और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिये अन्य संस्थानों के साथ 16 करार किये हैं। इन संस्थानों में दिल्ली विश्वविद्यालय, डेनिश कंसॉर्टियम फॉर एकैडमिक क्राफ्ट्समैनशिप, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी और राष्ट्रीय अपराध विज्ञान यूनिवर्सिटी शामिल हैं।
- लद्दाख विश्वविद्यालय के दो परिसरों में नये संकाय और प्रयोगशाला खंडों, खेल अवसंरचना, सभागार तथा कर्मचारी आवासों का निर्माण कर उनका विस्तार किया जा रहा है।
- संकाय विकास और छात्रों के आदान-प्रदान के कार्यक्रमों तथा अतिथि शिक्षकों के जरिये शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार किया जा रहा है। नुबरा और जंस्कार के महाविद्यालयों में दो खंड थे जिनका निर्माण तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के उच्चतर शिक्षा विभाग ने कराया था। सबसे बाद में स्थापित खालसी और द्रास महाविद्यालयों में कोई अवसंरचना नहीं थी।
- लद्दाख प्रशासन ने इन महाविद्यालयों की अवसंरचनाओं में सुधार का बीड़ा उठाया है। सिर्फ लेह के महाविद्यालय में 24 लड़कियों के लिये एक छात्रावास था। इसलिये सबसे पहले सभी महाविद्यालयों में लड़कों और लड़कियों के लिये छात्रावासों के निर्माण पर ध्यान दिया गया है।
- भारत सरकार ने नये संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के लिये विशेष विकास पैकेज दिया है। इसके तहत 2021-22 में महाविद्यालयों के लिये लगभग 200 करोड़ रुपये की अवसंरचना परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं।
- ये सभी निर्माण लद्दाख के लिये कार्बन निरपेक्ष दृष्टिकोण के अनुरूप ऊर्जा के न्यूनतम इस्तेमाल वाले हैं। इन्हें दिव्यांग छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। लद्दाख प्रशासन ने 2022-23 को दिव्यांगजन वर्ष घोषित किया है।

COPYING@OJAANKIAS

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 2021 में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी। इस विश्वविद्यालय का निर्माण खालसी में 110 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। यह विश्वविद्यालय लद्दाख के युवाओं को देश के अन्य भागों और विदेश के युवाओं के साथ अध्ययन का अवसर प्रदान करेगा।

छात्रवृत्ति

- लद्दाख प्रशासन ने छात्रों में मेधा और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2021 में रेवा योजना शुरू की। लद्दाखी शब्द रेवा का अर्थ उम्मीद होता है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 10 और 12 के मेधावी छात्रों को एक लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है चाहे उनकी पारिवारिक आय कितनी भी हो।
- छात्र इस धन का इस्तेमाल एनईईटी, जेईई, यूजी सीएलएटी और एनडीए जैसी राष्ट्र स्तरीय परीक्षाओं के लिये कोचिंग में कर सकते हैं।
- रेवा योजना के तहत सिविल सेवा, इंजीनियरी सेवा और वन सेवा जैसी परीक्षाओं के प्रारंभिक चरण में उत्तीर्ण छात्रों को भी 1.54 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। छात्र इस रकम का इस्तेमाल इन प्रतियोगिता परीक्षाओं के मुख्य चरण की कोचिंग के लिये कर सकते हैं।
- लद्दाख के लगभग 9363 छात्रों ने 2021-22 में अल्पसंख्यक और जनजातीय मामले मंत्रालयों की मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वजीफा हासिल किया। यह योजना लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के उन छात्रों के लिये हैं जो इन संघ शासित क्षेत्रों के बाहर मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं।

आईआईटी के साथ सहयोग

- लद्दाख के छात्रों को पहली दफा देश की प्रमुख शैक्षिक संस्था भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में इंटर्नशिप और एमटेक करने का मौका मिला है। संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के उच्चतर शिक्षा विभाग और आईआईटी समूह के बीच इस बारे में एक समझौता किया गया है।
- आईआईटी के कार्यक्रमों से लद्दाख के छात्रों को महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होगा। साथ ही उन्हें विभिन्न अवसरों को तलाशने, अपना उद्यमिता कौशल विकसित करने तथा अनुसंधान और विकास के लिये नये रास्ते बनाने में मदद मिलेगी। पांच साल- के लिये इन कार्यक्रमों को जून 2022 में शुरू किया गया है।
- लद्दाख के छात्रों के लिये तकनीकी शिक्षा के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से कारगिल में एक इंजीनियरी महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। इसके पाठ्यक्रम को तैयार करने तथा अवसंरचना, सांगठनिक ढांचे और मानव संसाधन की जरूरतों के बारे में सलाह देने के लिये आईआईटी से संपर्क किया गया है।

लद्दाख में कौशल विकास

- **कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अभिन्न अंग बनाया गया है। लद्दाख में भी कौशल विकास के तंत्र को मजबूत करने और विस्तार देने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।**
- **लद्दाख के दोनों जिलों में से हरेक में एक-एक औद्योगिक-प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और पॉलीटेकनिक महाविद्यालय है। आईटीआई में कुशल कामगारों की मौजूदा और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनमें 12 व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिनमें फैशन डिजाइन और प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली प्रबंधन, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक, बढ़ई, इलेक्ट्रिशियन तथा प्लंबर की ट्रेनिंग शामिल है।**
- **दोनों आईटीआई की अवसंरचना को मजबूत करने के लिये उनमें अत्याधुनिक उपकरणों से लैस नये कार्यशाला भवन बनाये जा रहे हैं।**
- **आईटीआई में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये प्रशिक्षकों की योग्यता में सुधार जरूरी है। इस दिशा में भी अनेक कदम**

उठाये गये हैं। अतिथि शिक्षकों को किये जाने वाले भुगतान में ढाई गुना बढ़ोतरी की गयी है। इसके अलावा संकाय के विकास तथा प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिये कार्यक्रम भी चलाये गये हैं।

- क्षेत्र की आवश्यकताओं और छात्रों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नये अवसरों की तलाश के लिये बागवानी और फूलों की खेती के दो नये कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। कुशल कामगारों की आपूर्ति और मांग के बीच तालमेल के लिये उद्योग के साथ सहयोग किया जा रहा है।
- लद्दाख कौशल विकास मिशन (एलएसडीएम) का 2021 में गठन किया गया। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और विभिन्न मंत्रालयों के अन्य कौशल विकास कार्यक्रमों के अधीन कार्यक्रम तैयार करना और उन्हें चलाना है। इससे राष्ट्रीय कौशल भारत अभियान के अनुरूप लद्दाख में कौशल विकास तंत्र को मजबूती और विस्तार मिलेगा।
- इस संघ शासित क्षेत्र में मार्च-अप्रैल 2021 में पहले कौशल मेले का आयोजन किया गया। इसका मकसद लद्दाख के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को तलाशने के अवसर मुहैया कराना था।
- लद्दाख में टेलीविजन और फिल्म- उद्योग का विकास हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप सौंदर्य और स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल श्रमशक्ति की मांग बढ़ सकती है।
- लद्दाख में कौशल की मांग और उपलब्धता का एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है जिसके जरिये उद्योग, प्रशिक्षण संस्थानों, ट्रेनिंग साझीदारों और युवाओं को एक मंच पर लाया जायेगा।

प्रशिक्षुता

- प्रशिक्षुता कानून के तहत 30 या इससे ज्यादा कामगारों वाले सभी संस्थानों के लिये प्रशिक्षुता कार्यक्रम चलाना और प्रशिक्षुओं को रखना अनिवार्य है। लद्दाख में इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन इसी साल जून में एक आदेश जारी किये जाने के साथ ही हुआ है।
- प्रशिक्षुता कानून उन युवाओं को अनुभव प्राप्त करने का अवसर देता है जिन्होंने स्नातक की पढ़ाई हाल में पूरी की है। इस कानून में उद्योग को महाविद्यालयों और आईटीआई से हाल में उत्तीर्ण युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। छात्र प्रशिक्षुता के जरिये अपनी पसंद का कौशल हासिल करने के साथ ही धनार्जन भी कर सकते हैं।
- वर्ष 2022-23 में प्रशिक्षुता की शुरुआत होने के कारण लेह और कारगिल के लिये छोटा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आने वाले वर्षों के लिये लक्ष्य प्रशिक्षुता में प्रगति और क्षेत्र के युवाओं की प्रतिक्रिया के आधार पर तय किये जाएंगे।

उद्यमिता शिक्षा

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा में उद्यमिता शिक्षण को शामिल करने पर जोर दिया गया है। लद्दाख में उच्चतर शिक्षा संस्थानों और आईटीआई में उद्यमिता को क्रेडिट आधारित विषय के रूप में शामिल करने के लिये विस्तृत परियोजना तैयार की जा रही है।
- इस संघ शासित प्रदेश के उद्योग विभाग ने कई कदम उठाये हैं। इनमें लद्दाख तैयारी केंद्र की स्थापना, चमड़े के सामान बनाने का प्रशिक्षण तथा फलों, हथकरघा उत्पादों और हस्तशिल्प के लिये निर्यात बाजार की तलाश शामिल है।
- उसने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) के साथ करार करने के अलावा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) के सहयोग से शिल्प दस्तावेजीकरण और ब्रांडिंग गतिविधियां शुरू की हैं। वाणिज्य मंत्रालय के साथ मिल कर खरीददारों और विक्रेताओं की सुविधा के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।
- उद्योग विभाग ने वाणिज्य सप्ताह और उद्यमिता विकास सम्मेलन का आयोजन करने के अलावा पशमीना बुनकरों के क्षमता निर्माण और ब्रांड लद्दाख के सृजन के लिये खादी और ग्रामोद्योग आयोग का सहयोग लिया है।

डिजिटलीकरण

COPYING@OJAA

- म्मू-कश्मीर में स्कूली शिक्षा का विस्तार 200 शिक्षा क्षेत्रों और 200 क्षेत्रीय संसाधन केंद्रों तथा 800 क्लस्टर शिक्षण क्षेत्रों में फैला है। इस केंद्रशासित प्रदेश में 14,171 प्राथमिक स्कूल, 6,665 अपर प्राइमरी स्कूल, 1,194 हाई स्कूल, 597 हायर सेकेंडरी (उच्चतर माध्यमिक) स्कूल, 2 सैनिक स्कूल, 22 ज़िला शिक्षण संस्थान और 2 राज्य शिक्षा संस्थान तथा 97 केजीबीवी हैं।'
- 2020 में महामारी के कारण समूचे विश्व में शिक्षा तंत्र मजबूरन एकदम अचानक बंद करने पड़े थे। ऐसी स्थिति में जम्मू-कश्मीर में भी स्कूल बंद करने पड़े और आमने-सामने पढ़ने की बजाय बच्चों को ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए पढ़ाने का विकल्प अपनाया गया।
- जम्मू के स्कूली शिक्षा विभाग के निदेशालय ने वैश्विक महामारी के दौरान भी बच्चों की शिक्षा जारी रखने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के उद्देश्य से 'डायरक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू होम क्लासेज' नाम से नई परियोजना चलाई।
- गूगल फॉर्म तैयार करके शिक्षकों को भेजे गए और उन्हें होम क्लासों में योगदान करने के लिए आमंत्रित किया गया। इन डिजिटल पहलों को लागू करने के वास्ते 'गूगलमीट, जूम, फेसबुक, व्हाट्सऐप और टेलीग्राम' जैसी विभिन्न एप्लीकेशंस इस्तेमाल की गई। सरकार ने जम्मू-कश्मीर में कोविड-19 के दौरान और कई पहले शुरू की। ये पहले हैं:

सरल, एंड्रॉयड ऐपः

- सरल अर्थात् विद्यार्थी पहुंच संसाधन और शिक्षण एप्लीकेशन (ऐप) जम्मू के स्कूली शिक्षा निदेशालय की आईटी विंग (सूचना टेक्नोलॉजी शाखा) ने 'ऑल-इन-वन' यानी 'एक ही में सब कुछ' की अवधारणा से विकसित की थी।
- यह ऐप विद्यार्थियों को ई-कंटेंट से जोड़ देता है जो दीक्षा, ई-पाठशाला, सय ई-विद्यादान और स्वयंप्रभा जैसे विभिन्न शिक्षा पोर्टलों पर उपलब्ध हैं। इससे विद्यार्थियों को स्थानीय तौर पर विकसित ई-कंटेंट, लाइव क्लासेज़, गतिविधियों और ऑनलाइन मूल्यांकन (आकलन) से भी जोड़ दिया जाता है।
- ई-कंटेंट अनेक सु-प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों ने तैयार किया था। इसके माध्यम से जम्मू-कश्मीर स्कूली शिक्षा बोर्ड (जेकेबीओएसई) द्वारा तैयार कराई पाठ्य पस्तकें भी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर 'सरल डीएसईजे ऑनलाइन एजुकेशन' नाम से उपलब्ध है।

स्कूल ट्रैकिंग और मॉनीटरिंग प्रणाली 'आधारशिला':

- आधार शिला वेब-आधारित प्रणाली है जिसका डिज़ाइन जम्मू के स्कूली शिक्षा निदेशालय ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य जम्मू डिवीजन के सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल व्यवस्था लागू करना है। इस वेब-आधारित प्रणाली से इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों और शिक्षण कार्य में उनकी दक्षता का आकलन करने में मदद मिलती है।
- इस वेब पोर्टल में सभी सरकारी स्कलों के विद्यार्थियों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। इस जानकारी से शिक्षक-विद्यार्थी अनपात, विद्यार्थियों का श्रेणीवार विवरण, स्कॉलरशिप का विवरण, आधार विवरण के बिना वाले विद्यार्थियों की पूरी जानकारी वगैरह' का पता चल जाता है। जिससे आगे की योजना बनाने और नीतिगत फैसले लेने में सविधा हो जाती है।
- इस वेब-आधारित पोर्टल पर राज्य और जिला स्तर से मिलने वाली आर्थिक सहायता का स्कूल-वार विवरण भी उपलब्ध रहता है। इस पोर्टल का वेब पता है- समाधान: समाधान शिकायतों की ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था है जिसका उद्देश्य डिलीवरी तंत्र, विशेषकर स्कूली शिक्षा के डिलीवरी तंत्र को पारदर्शी बनाना और उसमें सुधार लाना है।
- इस प्रणाली का डिज़ाइन डीएसई ने तैयार किया जिसे राष्ट्रीय अधिसूचना केंद्र (एनआईसी) ने विकसित किया। अभिभावक, विद्यार्थी और शिक्षक अपनी शिकायतें इस प्रणाली में भेज सकते हैं। इन शिकायतों को सुनवाई और निपटारे के लिए सबद्ध अधिकारियों के पास भेज दिया जाता है।

COPYING@OJAANKIAS

जम्मू-कश्मीर शिक्षा हबः

- जेएंडके एजुकेशन हब यानी जम्मू-कश्मीर शिक्षा हब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों द्वारा विकसित शक्षिक डिजिटल सामग्री की वेब-आधारित प्रणाली है। इस पर उपलब्ध उत्कृष्ट सामग्री चुनकर दीक्षा जैसे राष्ट्रीय स्तर के पोर्टलों पर भज दी जाती है।
- यह पोर्टल ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा को सुगम भार सरल बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। विद्यार्थी और शिक्षक अकेले इसी पोर्टल से सभी डिजिटल संसाधनों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल में एक विशेष भाग ऐसा है जिसमें शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपलब्धियों को दर्शाया जाता है।
- जम्मू के स्कूली शिक्षा निदेशालय का ई-ऑफिस निदेशालय ने कार्यालय के कामकाज को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस खोला था। कार्यालय का कामकाज पेपरलेस यानी पूरी तरह से डिजिटल बनाने के उद्देश्य से एनआईसी ने यह ई-ऑफिस शुरू किया था।
- फाइलों के डिजिटीकरण को देखते हुए जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए यह प्रणाली अपनाई गई थी। फाइलों के आने-जाने की व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए की जाती है जिससे फाइल की स्थिति पर निगाह रखी जा सकती है।
- प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधन की प्रणाली प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधन में भी वेब-आधारित प्रणाली लागू है। यह सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए लागू है चाहे वे जेकेबीओएसई, सीबीएसई या आईसीएसई में से किसी बोर्ड के अंतर्गत चलाए जा रहे हों। इस प्रणाली में प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन और अपग्रेडेशन (पंजीकरण और उन्नयन) की अनुमति भी ऑनलाइन देने की व्यवस्था है।
- यह पहल अभी विकसित की जा रही है और शीघ्र ही इसके पूरा हो जाने की उम्मीद है। 2 डिजिटल पहलों के अंतर्गत डीएसई जम्मू ने 25 से 31 जुलाई, 2022 तक 'डिजिटल जम्मू-कश्मीर सप्ताह मनाया जिसमें जम्मू-कश्मीर को डिजिटल बनाने में सरकार द्वारा चलाई गई डिजिटल पहलों का उल्लेख करने पर विशेष बल दिया गया था। जम्मू-कश्मीर सरकार शिक्षा व्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने और इसमें अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अनूठी डिजिटल पहले अपना रही है।

आकाश से परे

- अंतरिक्ष विज्ञान और उसके अनुप्रयोगों को समझने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश के विभिन्न भागों में कई संस्थान स्थापित किए हैं। उनमें जम्मू और कश्मीर शामिल है जहां इसरो और जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहयोग से एक उन्नत अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र (एसडीसीएसएस) जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।
- सीयूजे में एसडीसीएसएस की स्थापना इसके उत्तर भारत में प्रमुख केंद्र होने के नाते जम्मू-कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह केंद्र इस क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष अनुप्रयोगों की क्षमता का दोहन करने में मदद करेगा और युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान के साथ-साथ राष्ट्र के विकास में योगदान करने का अवसर प्रदान करेगा।
- अंतरिक्ष अनुप्रयोगों का दायरा जम्मू-कश्मीर और बृहत्तर हिमालयी क्षेत्र के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था और निवास स्थल वनस्पति आच्छादन, वन क्षेत्र, हिम, भूस्खलन, हिमस्खलन, भूजल, मेघावरण, वायुमंडलीय परिस्थितियों आदि से प्रभावित हैं और इन पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) के जरिए अंतरिक्ष से आसानी से नजर रखी जा सकती है।
- इस केंद्र में स्थित रिमोट सेंसिंग और जीआईएस प्रयोगशालाएं वायु प्रदूषकों और कणाकार पदार्थों की स्थिति और पूर्वानुमान का मूल्यांकन करने में सहायक हैं।
- साथ ही वे तापमान उत्क्रमण और वायुमंडलीय स्थिरता के साथ उनके परस्पर सम्बन्ध का पता लगाती हैं और मेसोस्केल वायुमंडलीय मॉडल और 3डी-वीएआर डाटा एसिमिलेशन तकनीक का उपयोग करके जम्मू-कश्मीर के मौसम की घटनाओं की मेसास्केल मॉडलिंग करती हैं।
- क्षेत्र में बारम्बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए मौसम और वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए इस क्षेत्र की भू-आधारित पर्यवेक्षण क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता का भी अत्यन्त महत्व है।

COPYING@OJAANKIAS

- सीयूजे के सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र में भू-स्थानिक डाटा विश्लेषण की सुविधाएं होंगी जो प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और भूमि-उपयोग पैटर्न की योजना बनाने में मदद करेंगी। इसमें वायुमंडलीय अध्ययन के लिए भू-आधारित पर्यवेक्षण सुविधाएँ होंगी।
- यहाँ खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय संवेदन के लिए एक शोध प्रयोगशाला के अलावा उत्तर भारत की नदियों में मौसमी हिम, बर्फ और हिमनदों के रूप में संग्रहित बड़ी मात्रा में जल के बेहतर उपयोग के लिए ग्लेशियर अध्ययन प्रयोगशाला होगी।
- यहां आपदा प्रबन्धन केंद्र भी स्थापित किया जाएगा जो जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में बाढ़, भूस्खलन, जंगल में लगने वाली आग, सूखा और जलवायु परिवर्तन जैसी विभिन्न आपदाओं पर अनुसंधान करेगा।
- यह केंद्र जम्मू और कश्मीर के आस-पास के क्षेत्र में जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना पर बायोएरोसोल के विविध प्रभावों का पता लगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- एसडीसीएसएस जम्मू और कश्मीर में स्थापित अपनी तरह का पहला संस्थान है। यह केंद्र अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा के लिए नए तरीकों की एक विशाल श्रृंखला प्रदान करता है।
- सहायक प्रौद्योगिकी से लाभान्वित विशेष आवश्यकताओं वाले जम्मू-कश्मीर के शिक्षित लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे।

हनले अंतरिक्ष वेधशाला

- पाक हालिया अध्ययन में कहा गया है कि लद्दाख में लेह एके पास हनले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला (आईएओ) विश्व स्तर पर सबसे उदीयमान वेधशाला स्थलों में से एक बन रहा है।
- यह इसके लाभों जैसे अधिक साफ़ रातें, न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण, हवा में तरल बूंदें यानी एरोसोल की सघनता, अत्यंत शुष्क वायुमंडलीय स्थिति और वर्षा से अबाधित होने के कारण है।
- **खगोलविद् कई वर्षों के दौरान एकत्रित स्थानीय मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर अपने आगामी बड़े टेलिस्कोप बनाने के लिए दुनिया भर में उपयुक्त स्थानों की लगातार खोज कर रहे हैं। इस तरह के अध्ययन भावी वेधशालाओं की योजना बनाने और यह पूर्वानुमान लगाने में महत्वपूर्ण हैं कि वे समय के साथ कैसे बदलेंगे।**
- **भारत के शोधकर्ताओं और उनके सहयोगियों ने 8 ऊँचाई वाले वेधशालाओं में रात्रिकाल के बादलों के जमघट के अंश का विस्तृत अध्ययन किया जिसमें भारत में तीन यानी हनले आर मरक (लद्दाख) और देवस्थल (नैनीताल) में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला (आईएओ) शामिल हैं।**
- **दिग्पा-रत्सा री, हनले का राष्ट्रीय वेधशाला के लिए सभावित स्थल के रूप में चयन भारतीय उपमहाद्वीप पर मौसम सबंधी स्थितियों के अध्ययन, हिमालय और ट्रांस-हिमालयी क्षत्रा में उच्च ऊँचाई वाले इलाकों के स्थलाकृतिक मानचित्रों क अध्ययन और साथ-साथ सितंबर 1993 में छह सम्भावित स्थलों के टोही सर्वेक्षण के बाद किया गया था।**
- **इसके अतिरिक्त जनवरी और जून 1994 में संस्थान के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इस स्थल के दौरे किये। स्थायी स्थल सर्वेक्षण शिविर दिसंबर 1994 में दिग्पा-रत्सा री के उत्तर में नीलमखुल मैदानी क्षेत्र के सिरे पर स्थापित किया गया था। स्थल का विस्तृत निरूपण जनवरी 1995 में शुरू हुआ और आज तक जारी है।**
- दिग्पा-रत्सा री की सबसे ऊँची चोटी 4517 मीटर की ऊँचाई पर है और इसका नाम सरस्वती पर्वत रखा गया है। आसपास का नीलमखुल मैदानी क्षेत्र समुद्र तल से 4240 मीटर की ऊंचाई पर है।
- यह शृंखला 2 कि.मी. पूर्व-पश्चिम और 1 कि.मी. उत्तर-दक्षिण में फैली है जिसका शीर्ष लगभग आधा वर्ग कि.मी. समतल क्षेत्र है। चोटी में कुछ चट्टानी टीले हैं जिन्हें कुछ मीटर तक समतल किया गया है। दो मीटर चौड़ाई वाला हिमालयी चंद्र टेलीस्कोप (एचसीटी) का स्थान शिखर के पूर्व में एमएसएल से 4500 मीटर की ऊँचाई पर है।

- विभिन्न खगोल-जलवायु मापदंडों के कई वर्षों के आंकड़ों की जांच करने के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (आईआईए) ने 2000 में भारतीय खगोलीय वेधशाला (आईएओ), हनले में 2-मीटर एपर्चर वाला हिमालयी चंद्र टेलीस्कोप (एचसीटी) स्थापित किया।

COPYING@OJAANKIAS

हिंदी साहित्य
द्वारा : श्री समीरात्मज मिश्रा
प्रख्यात लेखक एवं पूर्व BBC पत्रकार
निबंध मंजूषा McGraw Hill
बम्पर ऑफर
कक्षा कार्यक्रम- 45,000 30,000/-
Live/Online Fees- 40,000
प्रथम 100 छात्रों के लिए 30,000/-
www.ojaankedu.com
निबंध मंजूषा
Ojaank Sir
द्वारा : श्री समीरात्मज मिश्रा
Live On
ojaankEDU APP
App Store
Google Play
18/4, 3rd Floor Opposite Aggarwal Sweet
Near Gol Chakkar, Old Rajinder Nagar, New Delhi.
8750711100/22/33/44
7678528990

1YEAR COMPLETE
YOJANA &
Kurukshetra
Discount
Fee- 2000/-
1500/
Recorded Class
Limited
Offer
UPSC CSE 2021-2022
AIR-1 (SHRUTI SHARMA)
18/4, 3rd Floor Opposite Aggarwal Sweet, Near
Gol Chakkar Old Rajinder Nagar, New Delhi.
www.ojaankedu.com
Google Play
App Store
8750711100/22/33/44, 76785 28990

इतिहास
SPECIAL OFFER
वैकल्पिक विषय
निर्देश भारद्वाज सर के द्वारा
Classroom Fees - 45,000 30,000/-
Online/ Live - 40,000 30,000/-
LIVE ON ojaankEDU APP
Google Play
App Store
ऑनलाइन/कक्षा कार्यक्रम
18/4, 3rd Floor Opposite Aggarwal Sweet
Near Gol Chakkar Old Rajinder Nagar
New Delhi.
www.ojaankedu.com
8750711100/22/33/44, 7678528990
Our Topper (Air-1)
Optional History

SOCIOLOGY
OPTIONAL
By Ankur Aggarwal Sir
BUMPER
OFFER
FEE Discount
For 100 Students
Classroom Fees - 45,000 30,000/-
Online/ Live - 40,000 30,000/-
Online/Classroom
UPSC CSE 2021-2022
AIR-1(SHRUTI SHARMA)
18/4, 3rd Floor Opposite Aggarwal Sweets
Near Gol Chakkar Old Rajinder Nagar, New Delhi.
8750711100/22/33/44, 7678528990
Google Play
App Store
www.ojaankedu.com

TARGET UPSC PRELIMS (GS) 2023
एक बार TRY तो बनता है
आज का ऑफर
SCAN THE QR CODE
TO PAY
Offer Valid 28-09-22
रात 12 बजे तक
₹99/- Only
UPSC 2021
AIR-1
SHRUTI SHARMA
Online/ Live
Bilingual
Batch Start From
15 Nov 2022
www.ojaankedu.com
8750711100/22/33/44, 7678528990

OJAANK IAS ACADEMY
ADVANCE
NCERT
PRELIMS TEST SERIES
Was 2999/-
499/-
OUR TOPPERS
SHRUTI SHARMA
87-50-7-111-00/22/33/44, 76-785-289-90
Website : www.ojaankedu.com
REGISTER NOW